सांध्य दैनिक
4PM
जिद...सच की
www.4pm.co.in www.facebook.com/4pmnewsnetwork @Editor_Sanjay YouTube @4pm NEWS NETWORK
● वर्ष: 8 ● अंक: 158 ● पृष्ठ: 8 ● लखनऊ, गुरुवार, 14 जुलाई, 2022
मूल्य ₹ 3/-

हम बाहरी दुनिया में कभी शांति नहीं पा सकते हैं, जब तक की हम अन्दर से शांत न हों।

-दलाई लामा

कुमार विश्वास की बढ़ाई गई सुरक्षा... 7 | 2024 का रण: अब सोनिया और... 3 | असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटका... 2

मानसून सत्र से पूर्व असंसदीय शब्दों को लेकर जारी बुकलेट पर भड़का विपक्ष, कहा

विपक्षियों के बोलने पर प्रतिबंध लगा रही सरकार

» कांग्रेस, शिवसेना और तृणमूल कांग्रेस ने केंद्र की मंशा पर उठाए सवाल

» प्रतिबंधित किए गए हैं जुमलाजीवी, जयचंद, भ्रष्ट जैसे शब्द

» प्रतिबंधित शब्दों का लोक सभा और राज्य सभा में नहीं किया जा सकेगा इस्तेमाल, 18 जुलाई से शुरू होगा मानसून सत्र

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नई दिल्ली। संसद के मानसून सत्र से पहले लोक सभा सचिवालय द्वारा असंसदीय शब्दों को लेकर जारी नई बुकलेट पर सियासत गर्म हो गयी है। असंसदीय शब्दों में कुछ नए शब्द शामिल किए जाने पर विपक्ष आगबबूला हो गया है। कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस और शिवसेना ने इसको लेकर केंद्र की भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। विपक्षी नेताओं का कहना है कि भाजपा विपक्ष द्वारा संसद में इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों को प्रतिबंधित कर भारत को नष्ट कर रही है और विपक्षियों को बोलने से रोक रही है।

तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा ने ट्वीट किया, बैठ जाएं। बैठ जाइये। प्रेम से बोलें। लोक सभा और राज्य सभा की नई असंसदीय शब्दों की सूची में संघी शब्द शामिल नहीं है। मूल रूप से सरकार ने विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए गए सभी शब्दों के इस्तेमाल को रोकने के लिए यह काम किया है। कैसे भाजपा भारत को नष्ट कर रही है और उन पर प्रतिबंध लगा रही है। शिवसेना की राज्य सभा सदस्य प्रियंका चतुर्वेदी ने पुराने मीम का जिक्र कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने ट्वीट किया, यह पुराना मीम याद आ गया। अगर करें तो करें क्या, बोलें तो बोलें क्या? सिर्फ वाह मोदी जी वाह! यह मीम अब हकीकत सा लगता है।

कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, 'मोदी सरकार की सच्चाई दिखाने के लिए विपक्ष द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सभी शब्द अब 'असंसदीय' माने जाएंगे। अब आगे क्या?' कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया,

इनका भी नहीं कर सकेंगे इस्तेमाल

इस संकलन में अंग्रेजी के कुछ शब्दों एवं वाक्यों को भी शामिल किया गया है जिनमें आई विल कर्स यू, ब्रेट्रेड, ब्लडशेड, पिटेड, शेडिंग क्रोकोडाइल टियर्स, डंकी, गून्स, माफिया, रबिश, स्नेक चार्मर आदि शामिल हैं।

ये शब्द आएंगे अमर्यादित आचरण की श्रेणी में

लोक सभा सचिवालय ने असंसदीय शब्द, 2021 शीर्षक के तहत ऐसे शब्दों एवं वाक्यों का नया संकलन तैयार किया है, जिन्हें असंसदीय अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखा गया है। 18 जुलाई से शुरू हो रहे संसद के मानसून सत्र से पहले सदस्यों के इस्तेमाल के लिए जारी किए गए इस संकलन में ऐसे शब्दों या वाक्यों को शामिल किया गया है, जिन्हें लोक सभा, राज्य सभा और राज्यों के विधान मंडलों में वर्ष 2021 में असंसदीय घोषित किया गया था। इसके अनुसार, असंसदीय शब्द, वाक्य या अमर्यादित अभिव्यक्ति की श्रेणी में रखे गए शब्दों में कमीना, काला सत्र, दलाल, खून की खेती, दोहरा चरित्र, निकम्मा, नौटंकी, ढिंढोरा पीटना, बहरी सरकार, चिलम लेना, छोकरा, कोयला चोर, गोरू चोर, चरस पीते हैं, सांड, खालिस्तानी, विनाश पुरुष, तानाशाही, तानाशाह, अराजकतावादी, घड़ियाली आंसू जैसे शब्द भी शामिल किए गए हैं।

नहीं रखा जाएगा रिकॉर्ड

अध्यक्ष व सभापति पीठ पर आरोप को लेकर भी कई वाक्यों को असंसदीय श्रेणी में रखा गया है। इसमें आप मेरा समय खराब कर रहे हैं, आप हम लोगों का गला घोंट दीजिए आदि शामिल हैं। इन्हें रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं माना जाएगा।

'अगर आप अपनी आलोचना में रचनात्मक नहीं हो सकते तो संसद का क्या मतलब है? शब्दों पर प्रतिबंध लगाना अनुचित है। दरअसल, संसद के मानसून सत्र से पहले लोक सभा सचिवालय ने असंसदीय शब्दों को लेकर नई बुकलेट जारी की है। इसमें जुमलाजीवी, बाल बुद्धि, कोविड स्प्रेडर और स्नूपगेट, शर्म, दुर्व्यवहार, विश्वासघात, भ्रष्ट, ड्रामा, शकुनि, जयचंद पाखंड और अक्षम जैसे शब्द अब लोक सभा और राज्य सभा में असंसदीय माने जाएंगे।

सीएम ने बढ़ाया कोटेदारों का लाभांश, कहा

प्रदेश में जनसेवा केंद्र के रूप में काम करेंगी कोटे की दुकानें

» गोरखपुर में मुख्यमंत्री योगी ने किया योजना का शुभारंभ

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार एवं सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लि. के मध्य एमओयू और उचित दर विक्रेताओं के लाभांश में वृद्धि के संबंध में आयोजित कार्यक्रम का आज शुभारंभ किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार में राशन कोटे की दुकानों पर जनता को अब स्टांप बिक्री, बैंकिंग सेवा, आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र की भी सुविधा मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा, देश में यूपी अकेला ऐसा राज्य है जहां राशन वितरण की व्यवस्था सुचारु रूप से चल रही है। पहले कोटेदारों को लाभांश के रूप में 70 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान किया जाता था अब इसे बढ़ाकर 90 रुपये कर दिया गया है। प्रदेश की करीब 80 हजार कोटे की दुकानों को जनसेवा केंद्र (सीएससी) के रूप में विकसित किया जाएगा। इस दौरान खाद्य एवं रसद विभाग और केंद्र सरकार की कामन सर्विस सेंटर अथॉरिटी के बीच अनुबंध भी हुआ।

पकड़ा गया मालकिन की जान लेने वाला पिटबुल डॉग

» नगर निगम की टीम ले गई श्वान केंद्र

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। राजधानी में हमला कर अपनी मालकिन की जान लेने वाला पिटबुल डॉग आज पकड़ लिया गया। नगर निगम की टीम ने आज कैसरबाग स्थित बंगाली टोला में पिटबुल को पकड़ लिया और जरहरा स्थित श्वान केंद्र में लेकर चली गई।

नगर निगम के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी व संयुक्त निदेशक पशु कल्याण डॉ. अरविंद राव व पशु चिकित्साधिकारी डॉ. अभिनव वर्मा ने बताया कि बुधवार को टीम पिटबुल को पकड़ने गई थी लेकिन परिवारवाले अस्थि विसर्जन के लिए बाहर गए थे। इस पिटबुल का लाइसेंस बना है कि नहीं अभी साफ नहीं हो पाया है। लाइसेंस बनाने का काम प्राइवेट पशु चिकित्सक करते हैं, ऐसे में वहां से भी जानकारी मंगाई जा रही है। नगर निगम में इस कुत्ते का रिकॉर्ड नहीं मिला है।

गौरतलब है कि कैसरबाग स्थित बंगाली टोला निवासी अपनी मालकिन बुजुर्ग सुशीला त्रिपाठी पर दो दिन पहले इस पिटबुल डॉग ने हमला कर दिया था। उनकी इलाज के दौरान मौत हो गयी थी।

असल मुद्दों से जनता का ध्यान भटका रही मोदी सरकार : प्रतापगढ़ी

» बोले, अग्निपथ योजना युवाओं के साथ छलावा

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी ने अपने गृह जनपद प्रतापगढ़ में मोदी सरकार पर करारा हमला किया। उन्होंने कहा कि महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी चरम पर है और सीमाएं असुरक्षित हैं। इन सब मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाने के लिए मोदी व योगी सरकार रोज नए-नए जुमले छोड़ती रहती है। प्रतापगढ़ जिला कांग्रेस कार्यालय पर आए इमरान ने कहा कि उनको प्रतापगढ़ से बहुत लगाव है।

वह यहां के जिला कांग्रेस कार्यालय के कायाकल्प के लिए भी पहल करेंगे, इसे चमकाएंगे। प्रतापगढ़ ही नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को मजबूत करने के लिए मिलकर काम करेंगे। उन्होंने राज्य सभा सदस्य प्रमोद तिवारी का उल्लेख करते हुए कहा कि उनके साथ मिलकर जनपद के विकास का नया खाका खींचा जाएगा। वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि अग्निपथ योजना युवाओं के साथ छलावा है, सेना में ठेकेदारी प्रथा की शुरुआत है। इसका कांग्रेस सदन से सड़क तक जमकर विरोध कर रही है। आगे भी करती रहेगी। कृषि कानून की तरह सरकार को इसे वापस लेना पड़ेगा। उदयपुर कांड की निंदा करते हुए राज्य सभा सदस्य ने कहा कि नफरत व हिंसा कोई करे, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस दौरान जिलाध्यक्ष डा. लालजी त्रिपाठी, पूर्व प्रदेश यूथ कांग्रेस अध्यक्ष डा. नीरज त्रिपाठी व पूर्व जिलाध्यक्ष बृजेंद्र मिश्र समेत लोगों ने इमरान का स्वागत किया। इसके बाद वह प्लाजा पैलेस पहुंचे। वहां जनसभा में भी मोदी सरकार और योगी सरकार पर तंज कसा। कहा कि मुख्यमंत्री योगी ने बयान दिया है कि एक वर्ग विशेष की जनसंख्या बढ़ रही है। उनकी बात फर्जी है। उनको आंकड़े देखकर बोलना चाहिए।

भाजपा सरकार चुन रही विवादित मुद्दे : मायावती

» जनसंख्या मुद्दे पर भाजपा लोगों को कर रही गुमराह

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती ने विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान पर हमला बोला है। मायावती ने कहा जब महंगाई आसमान छू रही है और बेरोजगारी के अभिशाप से परिवारों का जीवन दुखी है। ऐसे में जनसंख्या नियंत्रण जैसे दीर्घकालीन विषय पर लोगों को उलझाना भाजपा की कौन सी समझदारी है।

मायावती ने कहा कि ऐसे समय में जब आसमान छूती महंगाई, अति गरीबी व बढ़ती बेरोजगारी आदि के अभिशाप से परिवारों का जीवन दुखी, त्रस्त व तनावपूर्ण है तथा वे स्वंय ही अपनी सभी जरूरतों को सीमित कर रहे हैं, तब जनसंख्या नियंत्रण जैसे दीर्घकालीन विषय पर लोगों को उलझाना भाजपा की कौन सी समझदारी है? बसपा प्रमुख ने कहा कि जनसंख्या नियंत्रण दीर्घकालीन नीतिगत मुद्दा, जिसके प्रति कानून से कहीं ज्यादा जागरुकता की जरूरत, किन्तु भाजपा सरकारें देश की वास्तविक प्राथमिकता पर समुचित ध्यान देने के बजाय भटकाऊ व विवादित मुद्दे ही चुन रही हैं तो ऐसे में जनहित च देशहित का सही से कैसे भला संभव? जनता दुखी व बेचैन। बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सीएम योगी उस बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि अराजकता आबादी से नहीं बल्कि लोकतांत्रिक मूल्यों की बरबादी से उपजती है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि जनसंख्या नियंत्रण कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा हो पाए।

सपा संरक्षक से मिलकर राजभर हुए 'मुलायम'

» बेटे अरुण ने कहा- बुलाकर हमसे बात करें अखिलेश

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव से नाराजगी के बीच सुभासपा प्रमुख ओपी राजभर ने कल देर शाम मुलायम सिंह यादव से मुलाकात की है। मुलाकात के बाद वे यादव परिवार की तारीफ करते नजर आए। मुलायम सिंह से मिलकर वे अखिलेश के प्रति नरम दिखाई दिए। इस बीच ओपी राजभर के बेटे अरुण राजभर ने अखिलेश यादव पर हमला बोला है। अरुण ने यहां तक कहा कि गठबंधन रहेगा या नहीं यह अखिलेश यादव को ही तय करना है।

अगर उन्हें लगता है कि पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है तो हमें बुलाकर पूछना चाहिए। मुलायम से मुलाकात पर अरुण ने कहा कि नेताजी की पत्नी का निधन हुआ था। उसी को लेकर ओपी राजभर शोक संवेदना व्यक्त करने गए थे। मुलायम सिंह ने राजभर से यह भी पूछा कि सब ठीक चल रहा है। नेताजी हमेशा कहते हैं कि मेहनत करो। हम लोग लगातार मेहनत कर रहे हैं। अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए अरुण राजभर ने कहा कि सपा और सुभासपा एक दूसरे की सहयोगी हैं। हमारे गठबंधन में रालोद भी शामिल है। अगर किसी बैठक में एक सहयोगी को बुलाया जाएगा और दूसरे को नजरअंदाज किया जाएगा तो कोई भी आपत्ति दर्ज करेगा ही। अरुण ने कहा कि हम लोग विपक्ष की पार्टियां हैं। राष्ट्रपति पद के लिए विपक्ष के प्रत्याशी यशवंत सिन्हा के साथ विपक्ष की सभी पार्टियों के साथ बैठक होनी चाहिए। बैठक में पहले हमें भी बुलाया गया। फिर अचानक कह दिया गया कि बैठक कैंसिल हो गई है, जबकि ऐसा नहीं हुआ था।

पशुपालन विभाग में करोड़ों के घोटाले की होगी उच्च स्तरीय जांच

दवा खरीद में हेराफेरी पर सीएम गंभीर, दो वरिष्ठ आईएएस अफसरों को सौंपी जांच

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। बेजुबानों की दवा और अन्य सामग्री खरीदने में भ्रष्टाचार की अब उच्च स्तरीय जांच होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पशुपालन विभाग में धांधली को गंभीरता से लिया है और दो वरिष्ठ आईएएस अफसरों को जांच सौंपी है। कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह व अपर मुख्य सचिव कृषि व कार्मिक देवेश चतुर्वेदी से सात दिन में रिपोर्ट मांगी गई है। पशु रोग नियंत्रण के अफसरों ने 60 करोड़ सरकारी धन को लूटने के लिए पशुओं की घटिया दवा और अस्पतालों की सामग्री मुंहमांगे दामों पर खरीदी। उत्तर प्रदेश सरकार पशुओं को आश्रय देने व उनके इलाज आदि को लेकर बेहद गंभीर है, वहीं पशुपालन और पशु रोग नियंत्रण विभाग के अफसर योजनाओं को पलीता लगाने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे।

जम्मू-कश्मीर व उत्तराखंड की दवा आपूर्ति करने वाली कंपनियां कटघरे में हैं, क्योंकि राजकीय विश्लेषक उत्तर प्रदेश ने जांच में इन्हें अधोमानक यानी घटिया पाया है। संबंधित कंपनियों से दो वर्ष के लिए व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है और बची दवाएं वापस लेने के आदेश जून माह में जारी हो चुके हैं। यह भी अल्टीमेटम दिया गया था कि दवाओं की आपूर्ति में जितनी धनराशि कंपनियों ने ली है वह वापस लौटाएं अन्यथा भू-राजस्व की तरह वसूली की जाएगी। इसी बीच 2021-22 में राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनएडीसीपी) योजना के तहत सामग्रियों की खरीद में हर कदम पर खामियां सामने आ गई हैं। जिला स्तर पर इस्तेमाल की जाने वाली सामग्रियों की आपूर्ति मुख्यालय पशुपालन विभाग पर 26 जुलाई से 26 अगस्त 2021 तक कराई गई। ये सामग्री जिलों को आठ माह बाद 22 मार्च 2022 तक भेजी गई, इससे अतिरिक्त खर्च हुआ। इसमें आपूर्ति करने वाली मेसर्स जगदीश इंटरप्राइजेज व मेसर्स अभिनीश ट्रेडर्स की संलिप्तता की भी जांच करने के निर्देश हुए हैं। पशु चिकित्सालयों के लिए सामग्री खरीदने में भी करोड़ों की हेराफेरी हुई है। खरीद के लिए जिलों से मांगपत्र संबंधी कोई अभिलेख पत्रावली में नहीं है। सरकारी धन लूटने की जल्दबाजी में अफसरों ने एक के बाद एक कई गड़बड़ियां की हैं। विभाग ने एक्टिव कोल्ड बाक्सेस 1,27,770 रुपये प्रति नग की दर से खरीदा। इसी अवधि में मध्य प्रदेश के पशुपालन विभाग ने इन्हीं बाक्सेस को 47,250 व 49,500 रुपये में खरीदा, जबकि जम्मू-कश्मीर में 59,000 प्रति नग की दर से खरीदा गया। आर्डर जेम पोर्टल से किया गया और भुगतान मैनुअल हुआ।

देश को उन्नति की राह पर ले गई भाजपा : लोधी

» क्षेत्र में करेंगे बिना भेदभाव के विकास कार्य

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

रामपुर। सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने कहा कि भाजपा की केंद्र और प्रदेश सरकार ने प्रत्येक व्यक्ति के हित को ध्यान में रखते हुए तमाम योजनाएं बनाई हैं, जिसका सभी को लाभ मिल रहा है। भाजपा ने देश को उन्नति की राह पर ले जाने का कार्य किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि सरकार की योजनाओं को आमजन तक पहुंचाने का कार्य करें। आम से आम आदमी भाजपा सरकार में खुद को सुरक्षित महसूस कर रहा है।

योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचा है। उन्होंने मिलक विधानसभा क्षेत्र के ग्राम लोहा पट्टी, खाता नगरिया, रोरा कलां, रोरा खुर्द व रामपुर नगर के ग्राम नोगमा, दबका में बूथों पर चर्चा की और ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। इसके अलावा उन्होंने मिलक में पूर्व विधायक बीना भारद्वाज के आवास पर जाकर उनके स्वास्थ्य का हाल जाना। सांसद घनश्याम सिंह लोधी ने लोगों से कहा कि चुनाव में हमारा सभी धर्म जाति के लोगों ने साथ दिया है। इसके लिए सभी क्षेत्रवासियों का आभारी हैं। विश्वास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर जनता जिताएगी। क्षेत्र में बिना भेदभाव के विकास कार्य कराया जाएगा।

2024 का रण : अब सोनिया और मुलायम के गढ़ पर भाजपा की नजर

» पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को रणनीति पर काम करने के निर्देश

» जाति के हिसाब से मंत्रियों को दिया गया जिम्मा, 17 जुलाई से शुरू होगा अभियान

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। विधान सभा चुनाव में प्रचंड बहुमत के साथ प्रदेश की सत्ता में लगातार दूसरी बार लौटी भाजपा अभी से लोक सभा चुनाव की तैयारियों में जुट गयी है। सपा के गढ़ रामपुर और आजमगढ़ में लोक सभा उपचुनाव में जीत दर्ज करने के बाद भाजपा की नजर अब कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी और सपा संरक्षक मुलायम सिंह यादव के गढ़ पर उसकी नजर लग गयी है। भाजपा ने इसके लिए न केवल प्लान तैयार कर लिया है बल्कि पिछले लोक सभा चुनाव में हारी सभी सीटों पर बाजी मारने की रणनीति बनायी है। रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को जमीन पर काम करने के निर्देश दिए गए हैं।

भाजपा ने 2024 में होने वाले लोक सभा चुनाव के लिए अभी से कमर कस ली है। 2019 के लोक सभा चुनाव में यूपी की हारी हुई 14 सीटों पर कमल खिलाने की जिम्मेदारी चार केन्द्रीय मंत्रियों के समूह को दी गई है। केंद्रीय मंत्रियों का यह समूह सपा, बसपा और कांग्रेस के कब्जे वाली 14 लोक सभा सीटों पर 17 जुलाई से प्रवास करेगा। तीन दिवसीय प्रवास में हर सीट पर केंद्रीय मंत्री प्रवास करेंगे। सोनिया के गढ़ रायबरेली और मुलायम के गढ़ मैनपुरी पर भाजपा की विशेष नजर है। इन सीटों को जीतने के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। इन सीटों पर राष्ट्रीय स्तर के संगठन के पदाधिकारियों को लगाया गया है। मैनपुरी सीट पर केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह के साथ प्रदेश संगठन के चार पदाधिकारी, दो यूपी सरकार के मंत्री और बूथ स्तर पर बीस कार्यकर्ताओं की अलग से टीमें बनाई गई हैं। भाजपा प्रवक्ता मनीष शुक्ला का कहना है कि पार्टी आगामी लोक सभा चुनावों की सभी 14 सीटों पर जीत के लिए काम कर रही है। इसके लिए केन्द्र के मंत्री और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों को तैनात किया गया है। जिन सीटों पर जिस जाति का वोट ज्यादा है, वहां पर उसी हिसाब से उसी बिरादरी के बड़े पदाधिकारियों की तैनाती की गई है, जिससे वह नेता अपने समाज के वोटरों से मिलकर उनको भाजपा के पक्ष में लामबंद करें। 14 लोक सभा की हारी हुई सीटों पर भाजपा ने चार मंत्रियों के समूह बनाए हैं। यह मंत्री इसी माह में अपने प्रभार वाली लोक सभा सीटों के दौरे शुरु कर देंगे। प्रदेश संगठन के चार पदाधिकारी, दो यूपी सरकार के मंत्री और बूथ स्तर पर बीस कार्यकर्ताओं की अलग से टीमें बनाई गई हैं।

पिछले लोक सभा चुनाव में हारी सीटों पर बाजी मारने का बनाया प्लान

सीटों पर इन मंत्रियों की हुई तैनाती

सहारनपुर, नगीना और बिजनौर सीटों का रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव को जिम्मा दिया गया है। रायबरेली, मऊ घोसी, श्रावस्ती और अंबेडकरनगर सीटों की जिम्मेदारी कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर को सौंपी गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह को मुरादाबाद, अमरोहा, संभल और मैनपुरी की जिम्मेदारी दी गई है। जौनपुर, गाजीपुर, लालगंज की जिम्मेदारी केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी को सौंपी गई है।

आजमगढ़ और रामपुर विजय से उत्साहित भाजपा

सपा के गढ़ आजमगढ़ और रामपुर में भाजपा ने लोक सभा उपचुनाव में विजय श्री हासिल की। ये दोनों सीटें उसने सपा से छीनी हैं। इस पर शीर्ष नेतृत्व का कहना है कि यदि बेहतर रणनीति से काम किया जाए तो किसी भी लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। यही वजह है कि भाजपा इस विजय से पूरी तरह उत्साहित है। गौरतलब है कि आजमगढ़ में भाजपा प्रत्याशी दिनेश लाल यादव निरहुआ ने सपा के धर्मेंद्र यादव को शिकस्त दी थी जबकि रामपुर में सपा के वरिष्ठ नेता आजम खां के करीबी आसिम रजा को भाजपा प्रत्याशी घनश्याम लोधी ने पराजित किया था।

अवैध कॉलोनियां बसाने वालों पर योगी सरकार कसेगी शिकंजा

» जमीनें होंगी जब्त मकान होंगे बुलडोज

» बसाने वालों को किया जाएगा चिन्हित

» प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी का इंतजार

दिव्यभान श्रीवास्तव

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में अवैध कॉलोनियों पर अब जल्द ही बुलडोजर चलने वाला है, क्योंकि नियमों को ताक पर रखकर कॉलोनियों को बसाने वालों के खिलाफ योगी सरकार ने अपनी नजर टेढ़ी कर ली है। यूपी की योगी सरकार एक ऐसी नीति लागू करने वाली है, जिसके बाद से प्रदेश भर में जल्द ही अवैध कॉलोनियों की जमीन जब्त हो सकेगी। यूपी सरकार ने इन कॉलोनियों को बनाने अथवा बसाने वालों की गिरफ्तारी के साथ ही उसके खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद आवास विकास विभाग जल्द ही इसके लिए नई नीति लाने जा रहा है।

सूत्रों की मानें तो सरकार की इस प्रस्तावित नीति का ड्राफ्ट लगभग तैयार है और इस जल्द ही कैबिनेट की मंजूरी दी जाएगी। इतना ही नहीं, इस एक्शन के लिए आवास विकास विभाग ने प्रदेश भर में अवैध कॉलोनियों को चिन्हित करने के लिए सर्वे करने का भी फैसला किया है। सर्वे से फायदा यह होगा कि नीति लागू होने के बाद अवैध कॉलोनियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकेगी। माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद यूपी सरकार अवैध कॉलोनी को बसाने वालों के खिलाफ ताबड़तोड़ एक्शन लेगी और इससे अन्य लोगों में खौफ पैदा होगा। माना जा रहा है कि आवास विभाग द्वारा तैयार की जा रही नई नीति में अवैध कॉलोनी बसाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए विकास प्राधिकरण अधिनियम में संशोधन भी किया जा सकता है, जिसके आधार पर अवैध कॉलोनियां बसाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने, गिरफ्तारी करने, जुर्माना लगाने और अवैध कॉलोनी से संबंधित जमीनें जब्त करने का प्रावधान किया जाएगा।

अंकुश लगाने की तैयारी

आवास विकास के सूत्रों के अनुसार योगी सरकार ने अवैध कॉलोनियां पर सख्ती करना शुरू कर दिया हैं, कई जिलों में मकान ढहाए भी गए हैं। अवैध कॉलोनियों को बसने से रोकने और इसे बसाने वालों के खिलाफ कार्रवाई के लिए सात सदस्यीय समिति बनाते हुए रिपोर्ट मांगी गई है। यही नहीं, इससे पहले भी आवास विभाग अवैध कॉलोनियों को वैध करने और इस पर अंकुश लगाने के लिए कई बार संबंधित नीतियों में संशोधन कर चुका है लेकिन प्राधिकरणों के स्तर पर अधिकारियों और कॉलोनाइजरों की मिलीभगत से अवैध कॉलोनी बसाने का खेल जारी है इसलिए अब एक बार फिर से अवैध कॉलोनियों पर अंकुश लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों को और सख्त करके कॉलोनाइजरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की व्यवस्था की जा रही है।

सीधे दर्ज की जाएगी एफआईआर

एलडीए के पूर्व उपाध्यक्ष रहे अभिषेक प्रकाश ने अवैध कॉलोनियों को चिन्हित करवाया था। अधिकारियों ने जोनवार अवैध कॉलोनाइजर की सूची बनाकर रिपोर्ट भी सौंपी थी मगर कार्रवाई धरातल पर नहीं उतर पाई। यही नहीं हर 6 महीने के अंतराल में शहर की गूगल सेटेलाइट इमेज लेकर संकलित करने की भी तैयारी थी। तस्वीरों की मदद से अवैध निर्माण व अवैध कालोनियों का पूरा कच्चा चिट्ठा समय रहते ही खुल जाएगा। वहीं, इससे यह भी तय हो सकेगा की अवैध निर्माण होने के समयकाल में उस क्षेत्र में कौन अभियंता, सुपरवाइजर व संबंधित कर्मचारी तैनात थे तैनात थे। अब बताया जा रहा है कि योगी सरकार के प्लान में अवैध कॉलोनियां बसाने वालों पर सीधी एफआईआर की कार्रवाई होगी।

Sanjay Sharma
editor.sanjaysharma
@Editor_Sanjay

जिद... सच की

श्रीलंका संकट के मायने

श्रीलंका में हालात पूरी तरह बेकाबू हो चुके हैं। जनता के आक्रोश के सामने सत्ताधीशों की चूलें हिल चुकी हैं। महंगाई, बेरोजगारी से परेशान जनता ने न केवल राष्ट्रपति भवन पर कब्जा कर लिया बल्कि प्रधानमंत्री कार्यालय में भी घुस गए। लाखों लोगों के हुजूम के आगे सुरक्षा बल भी पस्त हो चुके हैं। स्थिति संभालने में नाकाम राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे देश छोड़कर भाग गए हैं तो पीएम रानिल विक्रमसिंघे ने बतौर कार्यवाहक राष्ट्रपति आपातकाल घोषित कर दिया है। श्रीलंका की ताजा स्थिति उन सत्ताधीशों के लिए भी संदेश है जो जनता के दुख-दर्द को नहीं समझते हैं। साथ ही इस बात पर भी चिंतन करने का संदेश है कि मुफ्त की योजनाओं से खजाना खाली करना और कर्ज से राज्य या देश को दिवालिया बनाने का परिणाम अंततोगत्वा श्रीलंका की राह पर ले जाएगा। सवाल यह है कि श्रीलंका की हालत ऐसी क्यों हो गयी? जन क्रांति क्यों हुई? श्रीलंका की सरकार अपने नागरिकों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में नाकाम क्यों रही? क्या सरकार की नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है? क्या श्रीलंका के ताजा संकट का असर भारत पर पड़ेगा? क्या चीन से लिए गए कर्ज, कोरोना और यूक्रेन-रूस युद्ध ने भी श्रीलंका को घुटनों पर ला दिया है?

श्रीलंका की स्थिति एक दिन में नहीं बिगड़ी। इसके लिए सबसे अधिक जिम्मेदार यहां की सरकार की नीतियां रही हैं। राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे सरकार ने रासायनिक खाद पर प्रतिबंध लगाकर आर्गेनिक खेती को अनिवार्य कर दिया। इससे फसलों पर नकारात्मक असर पड़ा और अन्न की कमी हो गयी। सरकार ने चीन से भारी ब्याज पर मनमानी कर्ज लिया और उसका दुरुपयोग किया। ब्याज चुकाने के लिए और कर्ज लिया गया। यहां की अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक योगदान पर्यटन उद्योग का है लेकिन कोरोना के कारण पर्यटकों की आवाजाही बंद हो जाने से हालत चिंताजनक हो गयी। लोग बेरोजगार हो गए। यूक्रेन और रुस युद्ध के कारण खाद्यान्न की आपूर्ति बाधित होने से भी श्रीलंका की स्थिति बिगड़ गयी। लोग महंगाई, खाद्यान्न संकट व पेट्रोलियम पदार्थों की किल्लत से कराह उठे हैं। राजपक्षे ने जनता को राहत देने के बजाय अपने उस कुनबे को बचाने की कोशिश की जो देश के तमाम महत्वपूर्ण पदों पर काबिज और भ्रष्टाचार में लिप्त रहा। विश्व बैंक ने भी श्रीलंका को मदद देने से इंकार कर दिया। लिहाजा जनता सड़क पर उतर आई। श्रीलंका संकट का असर भारत पर भी पड़ेगा क्योंकि यहां के नागरिक समुद्र के रास्ते भारत में घुसने की कोशिश करेंगे। जाहिर है श्रीलंका की ताजा स्थितियों से दुनिया के देशों को सबक सीखने की जरूरत है।

सवाल यह है कि श्रीलंका की हालत ऐसी क्यों हो गयी? जन क्रांति क्यों हुई? श्रीलंका की सरकार अपने नागरिकों की मूलभूत जरूरतों को पूरा करने में नाकाम क्यों रही? क्या सरकार की नीतियों ने देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया है? क्या श्रीलंका के ताजा संकट का असर भारत पर पड़ेगा? क्या चीन से लिए गए कर्ज, कोरोना और यूक्रेन-रूस युद्ध ने भी श्रीलंका को घुटनों पर ला दिया है?

(इस लेख पर आप अपनी राय 9559286005 पर एसएमएस या info@4pm.co.in पर ई-मेल भी कर सकते हैं)

विदेशी मुद्रा का प्रबंधन जरूरी

अजीत रानाडे

बीते आठ महीनों में विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने शेयर और बॉन्ड की बिकवाली कर लगभग 40 अरब डॉलर भारत से निकाल लिया है। इसी अवधि में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में 52 अरब डॉलर की कमी हुई है। अमेरिकी डॉलर की तुलना में भारतीय रुपये के मूल्य में गिरावट जारी है। निर्यात की अपेक्षा आयात में तेजी से वृद्धि हो रही है इसका मतलब है कि हमें भुगतान के लिए निर्यात से प्राप्त डॉलर से कहीं अधिक डॉलर की जरूरत है। सामान्य परिस्थितियों में भी भारत के पास डॉलर की संभालने लायक कमी रहती आयी है जो अमूमन सकल घरेलू उत्पादन (जीडीपी) का एक से दो प्रतिशत होती है। आम तौर पर यह 50 अरब डॉलर से कम रहती है और आयात से अधिक निर्यात होने पर इसमें बढ़ोतरी होती है। इस कमी की भरपाई शेयर बाजार में विदेशी निवेश, विदेशी कर्ज, निजी साझेदारी या बॉन्ड खरीद से की जाती है।

इस तरह से आनेवाली पूंजी हमेशा ही चालू खाता घाटे से अधिक रही है, जिससे भारत का 'भुगतान संतुलन' खाता अधिशेष में रहता है। विदेशी कर्ज और उधार से ही ऐसा अधिशेष रखना जरूरी नहीं कि अच्छी बात ही हो, खासकर तब दुनियाभर में कर्ज का दबाव है लेकिन सामान्य दिनों में विदेशियों का आराम से भारतीय अर्थव्यवस्था को कर्ज देना उनके भरोसे का संकेत है। यह सब तेजी से बदलने को है और भारत के विदेशी मुद्रा कोष के संरक्षक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेतावनी का शुरुआती संकेत दे दिया है अगर भाग्य ने साथ दिया और मान लिया जाये कि इस वित्त वर्ष में 80 अरब डॉलर की बड़ी रकम भी भारत में आये, तब भी भुगतान संतुलन खाते में 30-40 अरब डॉलर की कमी रहेगी। हमारा चालू खाता घाटा जीडीपी का 3.2 प्रतिशत तक होकर 100 अरब डॉलर के पार जा सकता है। विदेशी मुद्रा के इस अतिरिक्त दबाव को झेलने के लिए हमारा भंडार पूरा नहीं होगा इसीलिए रिजर्व बैंक ने अप्रवासी भारतीयों से डॉलर में जमा को आकर्षित करने के लिए कुछ छूट दी है। इसने विदेशी कर्ज लेना भी आसान बनाया है तथा भारत सरकार के बॉन्ड के विदेशी स्वामित्व की सीमा भी बढ़ा दी है। भारत का कुल विदेशी कर्ज 620 अरब डॉलर है और इसमें से 267 अरब डॉलर आगामी नौ माह में चुकाना है। कम अवधि के कर्ज का यह अनुपात 44 प्रतिशत है और खतरनाक रूप से अधिक है। कर्ज लेने वाली निजी कंपनियों को या तो नया कर्ज लेना

होगा या भारत के मुद्रा भंडार से धन निकालना होगा। दूसरा विकल्प वांछित नहीं है क्योंकि मुद्रा भंडार घट रहा है और उसे बढ़ाने की जरूरत है। पहला विकल्प आसान नहीं होगा क्योंकि डॉलर विकासशील देशों में जाने के बजाय अमेरिका की ओर जा रहा है। किसी भी स्थिति में नये कर्ज पर अधिक ब्याज देना होगा, जिससे भविष्य में बोझ बढ़ेगा। रिजर्व बैंक की पहलें केंद्र सरकार द्वारा डॉलर बचाने के उपायों के साथ की गयी हैं। सोना पर आयात शुल्क बढ़ाकर 12.5 प्रतिशत कर दिया गया है। बहुत अधिक मांग के कारण भारत दुनिया में सोने का सबसे बड़ा आयातक है। शुल्क बढ़ाने से मांग कुछ कम भले हो पर इससे तस्करी भी बढ़ सकती है। गैर-जरूरी आयातों पर कुछ रोक लगने की संभावना है ताकि डॉलर का जाना रुक सके। विदेशी मुद्रा और विनिमय दर का प्रबंधन रिजर्व बैंक की जिम्मेदारी है। अभी शेयर बाजार पर निवेशकों के निकलने के अलावा तेल की बढ़ी कीमतों के कारण भी दबाव है। इससे भारत का कुल आयात खर्च (सालाना 150 अरब डॉलर से अधिक) प्रभावित होता है तथा अनुदान खर्च भी बढ़ता है क्योंकि तेल व खाद के दाम का पूरा भार उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाता है। इस अतिरिक्त वित्तीय बोझ का सामना करने के लिए सरकार ने इस्पात और तेल शोधक कंपनियों के मुनाफे पर निर्यात कर लगाया है। इस कर से एक लाख करोड़ रुपये से अधिक के राजस्व संग्रहण की अपेक्षा है। यह रुपये के मूल्य में गिरावट के असर से निपटने का एक अप्रत्यक्ष तरीका है। राज्य सरकारों पर अपने कर्ज का भी बड़ा बोझ है और 10 राज्यों की स्थिति तो खतरनाक स्तर पर पहुंच चुकी है, जो उनके दिवालिया होने का कारण भी बन सकता है। ऐसे में भारतीय संप्रभु गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं, जो सोने का डिमैट विकल्प है और कीमती विदेशी मुद्रा भी बाहर नहीं जाती। सरकार को आक्रामक होकर बॉन्ड बेचना चाहिए। आगामी महीनों में घरेलू और बाहरी मोर्चों पर दोहरे घाटे के प्रबंधन के लिए ठोस उपाय करने होंगे। उच्च वित्तीय घाटा उच्च ब्याज दरों का कारण बनता है और उच्च व्यापार घाटा रुपये को कमजोर करता है. अगर दोनों घाटों को कम करने के लिए इन दो नीतिगत औजारों (ब्याज दर और विनिमय दर) पर काम किया जाता है, तो हम संकट से बच सकते हैं।

तकनीकी शब्दावली से समृद्ध होंगी भारतीय भाषाएं

अशोक उपाध्याय

केंद्र सरकार देश को शिक्षा के सीमित सोच के दायरे से निकालकर 21वीं सदी के आधुनिक विचारों से जोड़ना चाहती है जहां मेधा की कभी कमी नहीं रही है। केंद्र की यह चिंता वाजिब है कि यहां ऐसी व्यवस्था बना दी गई थी जिसमें पढ़ाई का मतलब केवल और केवल नौकरी ही माना जाने लगा था। प्रधानमंत्री मोदी का मत है कि शिक्षा में यह विकार गुलामी के कालखंड में अंग्रेजों ने अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए, अपने लिए एक सेवक वर्ग तैयार करने के लिए पैदा किया था। आजादी के बाद, इसमें थोड़ा-बहुत बदलाव तो हुआ लेकिन बहुत सारा बदलाव रह गया। अंग्रेजों की बनाई व्यवस्था कभी भी भारत के मूल स्वभाव का हिस्सा नहीं थी और न हो सकती है।

यह सवाल गौर करने योग्य है कि बौद्धिक दायरा किसी भाषा विशेष का ज्ञान रखने वालों तक ही सीमित क्यों रहना चाहिए। यह भावनात्मक मुद्दा नहीं है बल्कि इसके पीछे वैज्ञानिक कारण भी रहे हैं। दुनिया चौथी औद्योगिक क्रांति के दौर से गुजर रही है और पिछली तीन औद्योगिक क्रांति के अनुसंधान में हम पिछड़ गये। प्रधानमंत्री ने इसकी वजह गिनाते हुए स्पष्ट किया है कि गुलामी के कालखंड में भारतीय भाषाओं की उपेक्षा हुई और अनुसंधान की भाषा को सिर्फ एक-दो भाषाओं तक सीमित रखा गया। उन्होंने सभी भारतीय भाषाओं को धनी बनाने के सरकार के राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशन का जिक्र किया, जिसका मकसद साफ है कि भारतीय भाषाओं में तकनीकी शब्दावलियां उपलब्ध हों। इंटरनेट पर ज्ञान और सूचना का बहुत बड़ा भंडार है जिसे हर कोई अपनी भाषा में जान सके और इस मकसद को पूरा करने के लिये भाषीनी प्लेटफार्म लांच किया गया है। प्रधानमंत्री ने जिस भाषा का नाम नहीं लिया, वह अंग्रेजी है। भारत में मिशनरी स्कूलों की शुरुआत 16वीं सदी में हुई और पुर्तगालियों ने पहले गोवा और कोच्चि में ऐसे स्कूलों की स्थापना की। अंग्रेजी हुकूमत आने के बाद 18वीं सदी से मिशनरी स्कूलों का तेजी से विस्तार हुआ और आज ऐसे स्कूल एवं कॉलेज देश के लगभग हर बड़े शहर में मौजूद हैं। इन स्कूल-कॉलेजों में शिक्षा एवं बोलचाल की भाषा अंग्रेजी है और उसे बड़ी सख्ती से लागू किया जाता है। हर भाषा का अपना दायरा और महत्व है और भारत सदैव से अनगिनत भाषाओं को समाहित करने में सक्षम रहा है। भारत में हर भाषा फली-फूली है और बोलचाल से लेकर साहित्य रचना में उसका योगदान सर्वविदित है। नरेंद्र मोदी ने पिछले दिनों मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में अदालतों में स्थानीय भाषाओं के इस्तेमाल पर भी जोर दिया था। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी में न्यायिक प्रक्रिया और फैसले समझना मुश्किल होता है। स्थानीय भाषाओं के प्रयोग से न्याय प्रणाली में आम नागरिकों का विश्वास बढ़ेगा और वे इससे अधिक जुड़ाव महसूस करेंगे। यह एक तरह से सामाजिक न्याय होगा। 18वीं सदी के आरंभ होने तक भारत में हिंदी मुख्य भाषा नहीं थी और काफी हद तक संपर्क भाषा भी नहीं थी। मुख्य रूप से संस्कृत, अरबी और फारसी का कामकाज की भाषा के रूप में इस्तेमाल होता था। अंग्रेजी हुकूमत के आने के बाद गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने भारत को समझने के लिये हिंदी या उर्दू भाषा को नहीं बल्कि फारसी भाषा को प्राथमिकता दी। वास्तव में उसे आभास हो गया था कि भारत को समझने के लिये इसकी भाषाई विविधता को समझना और इनका संरक्षण अनिवार्य है। सांस्कृतिक विविधताओं से भरा भारत ऐसा देश है जहां हर चालीस कोस के बाद बोली और रहन-सहन में अंतर देखने को मिलता है। अंग्रेज अफसरों के लिए संस्कृत, अरबी और फारसी भाषा का ज्ञान अनिवार्य कर दिया गया था। आठ फरवरी, 1812 को जारी एक सरकारी अध्यादेश में स्पष्ट लिखा गया कि जनहित से जुड़े सरकारी पदों पर तैनात अफसरों के लिए तीनों भाषाओं का ज्ञान जरूरी है। प्रशासनिक सेवा के अफसरों को बाकायदा तीनों भाषाओं का प्रशिक्षण दिया जाता था। बीसवीं सदी तक भारतीय प्रशासनिक सेवा में इन्हीं तीनों भाषाओं का इस्तेमाल देखा जा सकता है। दरअसल उन्नीसवीं सदी में अंग्रेज शासन के दौरान अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने की कवायद शुरू हो गई, अंग्रेजी के साथ हिंदी एवं उर्दू का इस्तेमाल बढ़ता चला गया और संस्कृत, अरबी और फारसी का इस्तेमाल कम होता चला गया।

आजादी मिलने के बाद 1960 के दशक में हिंदी और क्षेत्रीय भाषाओं को लेकर राजनीतिक बवाल हुआ था। दक्षिण भारत के लोगों के मन में यह शंका पैदा की गई कि उन पर हिंदी थोपने की कोशिश की जा रही है जो पूरी तरह से आधारहीन थी। उस समय तक अंग्रेजी सरकारी भाषा का रूप ले चुकी थी, लेकिन आजाद भारत में एक राष्ट्रीय भाषा की जरूरत को महसूस किया गया, जिसकी वजह अपनी पहचान को बनाये रखना था। चूंकि आबादी के लिहाज से हिंदी सबसे ज्यादा बोली और समझी जाती थी इसलिये उसके विस्तार की कल्पना की गई। कभी किसी सरकार ने हिंदी को गैर-हिंदी भाषी लोगों पर थोपने की कोशिश नहीं की। दरअसल, केंद्र सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति में इन तमाम पहलुओं को समाहित करने के साथ देश की हर भाषा को धनी बनाने के लिए काम कर रही है। लेकिन इस हकीकत को ध्यान में रखना होगा कि औद्योगिक क्रांति के नये दौर में अनुसंधान के दस्तावेज अंग्रेजी में ज्यादा उपलब्ध होते हैं, ऐसे में उनका सटीक अनुवाद जरूरी है। केंद्र के साथ हर राज्य को अपनी क्षेत्रीय भाषा में इंटरनेट के युग के हिसाब से अनुवाद की सुविधा मुहैया कराने के लिये आगे आना चाहिए ताकि वे भविष्य में संरक्षित रहें।

मौसमी बीमारी से बचने के लिए पीएं

पपीते का जूस

देश में इन दिनों मानसूनी बारिश का दौर चल रहा है। मानसून में आसमान से बरसते पानी से गर्मी से राहत भले मिलती हो लेकिन इसी खूबसूरत मानसून का एक पहलू और भी है जो थोड़ा बहुत डराने वाला है। जो मौसमी बीमारियों के रूप में सामने आता है, जिनका समय रहते निदान करना बहुत जरूरी है। वैसे तो ऐसी कई सारी चीजें है जो आपको मौसमी बीमारियों से लड़ने की ताकत देती है। लेकिन पपीते के पत्ते का जूस, उन बीमारियों में किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं, जो आपकी इम्यूनिटी को बुरी तरह प्रभावित करते है। पपीते के पत्तों में विटामिन ए, सी, ई, के, बी और कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम और आयरन जैसे मिनरल्स होते हैं जो कि इम्यूनिटी बढ़ाते हैं और संक्रामक बीमारियों से बचाते हैं। तो आइए जानते है बारिश के मौसम में किस तरह की बीमारियों में पपीते के पत्ते का जूस औषधि के रूप में काम करता है।

वायरल फीवर

बारिश के मौसम में वायरल फीवर होना आम परेशानी है। जो लो इम्यूनिटी के कारण होता है। तो अगर आप किसी इम्यूनिटी बूस्टर की तलाश में है, तो पपीते के पत्तों से बना जूस आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। दरअसल, ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है जो कि वायरल फीवर से बचाव में मदद करता है और बरसात में होने वाली संक्रामक बीमारियों से बचाता है।

डेंगू

डेंगू को बारिश के मौसम में होने वाली सबसे आम बीमारियों में से एक कहा जा सकता है। डेंगू संक्रमित एडीज मच्छरों के कारण होता है, जो इस बीमारी को हमारे खून में पहुंचाते हैं। इससे डेंगू बुखार होता है जो कि खून में प्लेटलेट्स की संख्या कम कर देता है। ऐसी स्थिति में यदि पेशेंट को पपीते के पत्ते का जूस दिया जाए तो प्लेटलेट्स तेजी से बढ़ जाते है। और पेशेंट कुछ ही दिनों में बेहतर महसूस करने लगता है।

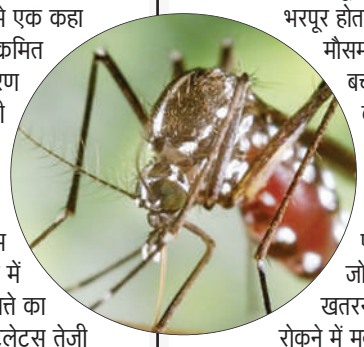

मलेरिया

पपीते के पत्तों से बना जूस एंटी ऐसे गुणों से भरपूर होता है जो बारिश के मौसम में मलेरिया से बचाव करने में मदद करता है। दरअसल, पपीते के पत्ते में पाया जाने वाला एक यौगिक एसिटोजिनिन होता है, जो मलेरिया जैसी खतरनाक बीमारी को रोकने में मदद कर सकता है। इसलिए बारिश में मलेरिया के बचाव के लिए पपीते के पत्ते का जूस जरुर पिएं।

पेट का इंफेक्शन

बरसात के मौसम में गंदा पानी या संक्रमित खाना खाने की वजह से पेट में इंफेक्शन की समस्या बढ़ जाती है। ऐसी स्थिति में पपीते के पत्ते के जूस का सेवन कई तरह से फायदा पहुंचाता है। क्योंकि इसमें एंजाइम पपैन और काइमोनपैपेन होते हैं। ये दोनों पेट संबंधी समस्याओं को दूर करने में मददगार है। दरअसल पपीते के पत्ते प्रोटीज और एमाइलेज से भी भरपूर होते हैं। ये एंजाइम पाचन में सहायता करने वाले प्रोटीन, कार्बस और खनिजों को तोड़ने में मदद करते हैं।

बरसाती घाव

पपीते के पत्ते का जूस लीवर के लिए एक पॉवरफुल क्लीनर के रूप में कार्य करता है, जिससे लीवर सही ढंग से काम कर पाता है। इससे शरीर के टॉक्सिन की सफाई होती है और खून भी साफ रहता है। बरसात में इस जूस को पीने से खून में एंटीबैक्टीरियल गुण रहता है जिससे स्किन से जुड़ी समस्याएं नहीं होती।

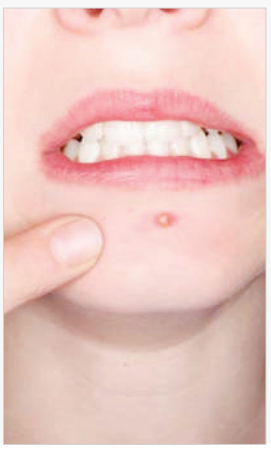

हंसना मना है

ट्रेन में पढ़ी जाने वाली किताबें

1AC: बिजनेस मैगजीन, मार्क्स, एडिसन, गॅलिलिओ, लिंकन, **2AC:** शेल्डन, ब्रुक्स, शेक्सपियर, रिस्टोटल, **3AC:** गांधी, ओबामा, अब्दुल कलाम, चेतन भगत, ओशो, अरुंधती रॉय, रॉबिन शर्मा, दीपक चोप्रा, शिव खेरा
Sleeper: क्रिकेट सम्राट तेंदुलकर, मनोरमा, फिल्म फेयर, बाबा रामदेव, अध्यात्म
General: प्रेमिका का बदला, खौफनाक हवेली, खूंखार रात, बेवफा से बदला लेने के 101 तरीके, मनचाही लड़की पटाने का तरीका, करंट मारे गोरिया, 30 दिन में डाक्टर कैसे बनें...

चिंटू और मिंटू बात करते हुए, **चिंटू:** यार कल रात घर देर से पहुंचा, बेल बजाई पर बीवी ने दरवाजा खोला ही नहीं! पूरी रात सड़क पर गुजारी। **पिंटू:** फिर सुबह बीवी की खबर ली की नहीं? **चिंटू:** नहीं यार, सबेरे दारू उतरी तो याद आया, अभी तो मेरी शादी ही नहीं हुई है, और चाबी तो जेब में थी!

मैनेजर: क्या कोई बता सकता है कि ऑनलाइन खाना बेचने वाली कंपनियां कैसे सफल हुईं? **पप्पू :** इसका क्रेडिट लाखों युवतियों द्वारा बनाए गए घिया, टिंडा, लौकी और तोरई को जाता है।

एक दिन पति ने पत्नी को शराब चखाई। **पत्नी:** यह तो बहुत कड़वी है। **पति:** ...तो तुम क्या समझती थी कि मैं अय्याशी करता हूं। जहर के घूंट पीता हूं, जहर के।

कहानी | बाबापुर की रामलीला

हर वर्ष दशहरे से पूर्व काशी की नाटक मंडली विजयनगर आती थी। सामान्यत: वे राजा कृष्णदेव राय तथा विजयनगर की प्रजा के लिए रामलीला किया करते थे। परंतु एक बार राजा को सूचना मिली कि नाटक मंडली विजयनगर नहीं आ रही है। इसका कारण यह था कि नाटक मंडली के कई सदस्य बीमार हो गए थे। यह सूचना पाकर राजा बहुत दु:खी हुए, क्योंकि दशहरे में अब कुछ ही दिन बाकी थे। इतने कम दिनों में दूसरी नाटक मंडली की भी व्यवस्था नहीं की जा सकती थी। पास में दूसरी कोई नाटक मंडली नहीं होने के कारण इस वर्ष रामलीला होने के आसार दिखाई नहीं पड़ रहे थे जबकि दशहरे से पूर्व रामलीला होना विजयनगर की पुरानी संस्कृति थी। महाराज को इस तरह दु:खी देखकर राजगुरु बोले, महाराज, यदि चाहें तो हम रामपुर के कलाकारों को संदेश भेज सकते हैं? परंतु, इसमें तो कुछ सप्ताह का समय लगेगा, राजा ने निराश स्वर में कहा। इस पर तेनालीराम बोले, महाराज, मैं पास ही की एक मंडली को जानता हूं, वे यहां दो दिन में आ जाएंगे और मुझे विश्वास है कि वे रामलीला का अच्छा प्रदर्शन करेंगे। यह सुनकर राजा प्रसन्न हो गए और तेनालीराम को मंडली को बुलाने की जिम्मेदारी सौंप दी गई, साथ ही मंडली के रहने व खाने-पीने की व्यवस्था का भार भी तेनाली के ही सुपुर्द कर दिया गया। शीघ्र ही रामलीला के लिए सारी व्यवस्था होनी शुरू हो गई। रामलीला मैदान को साफ किया गया। एक बड़ा-सा मंच बनाया गया। नवरात्र के लिए नगर को सजाया गया। रामलीला देखने के लिए लोग बहुत उत्सुक थे, क्योंकि इसके पूर्व काशी की नाटक मंडली के न आने की सूचना से वे काफी दु:खी थे, परंतु अब नई नाटक मंडली के आने की सूचना से उनका उत्साह दोगुना हो गया था। महल के निकट एक मेला भी लगाया गया था। कुछ ही दिनों में मंडली रामलीला के लिए तैयार हो गई। राजा, दरबारी, मंत्री व प्रजा प्रतिदिन रामलीला देखने आते। दशहरे के दिन की अंतिम कड़ी तो बहुत ही सराहनीय थी। मंडली में अधिकतर कलाकार बच्चे थे। उनकी कलाकारी देखकर लोगों की आंखों में आंसू तक आ गए। दशहरे के पश्चात राजा ने कुछ मंत्रियों तथा मंडली के सदस्यों को महल में भोजन के लिए बुलाया। भोजन के पश्चात राजा ने मंडली के सदस्यों को पुरस्कार दिया। फिर वे तेनालीराम से बोले, तुम्हें इतनी अच्छी मंडली कैसे मिली? बाबापुर से महाराज, तेनालीराम ने उत्तर दिया। बाबापुर! यह कहां है? मैंने इसके विषय में कभी नहीं सुना, राजा ने आश्चर्य से पूछा। बाबापुर विजयनगर के पास ही है, महाराज। तेनालीराम बोला। तेनालीराम की बात सुनकर मंडली के कलाकार मुस्करा दिए। राजा ने उनसे उनके इस प्रकार मुस्कराने का कारण पूछा तो मंडली का एक छोटा बालक सदस्य बोला, महाराज, वास्तव में हम लोग विजयनगर से ही आए हैं। तेनाली बाबा ने तीन दिन में हमें यह नाटक करना सिखाया था इसलिए इसे हम बाबापुर की रामलीला कहते हैं। यह सुनकर राजा भी खिलखिलाकर हंस पड़े। अब उन्हें भी बाबापुर के रहस्य का पता चल गया था।

5 अंतर खोजें

जानिए कैसा रहेगा कल का दिन

पंडित संदीप आत्रेय शास्त्री

लेखक प्रसिद्ध ज्योतिषविद हैं। सभी प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए कॉल करें-9837081951

मेष

आज का दिन आपको चौतरफा खुशी मिल सकती है। व्यावसायिक रूप से आप सक्रिय और सतर्क रहेंगे। विदेशों संपर्कों से आर्थिक लाभ संभव है।

वृषभ

आज का दिन जीवन में किसी नयी खुशी का संकेत लायेगा। आपका जीवनसाथी आपको कोई बड़ी खुशखबरी देगा। रिश्तों और काम के बीच तालमेल बना रहेगा।

मिथुन

व्यापारी वर्ग और नौकरी वालों के लिए आज का दिन लाभदायी निकलेगा। दिनचर्या में थोड़ा सा बदलाव भी आपको करना होगा। इससे आपकी समस्याएं सुलझ सकती हैं।

कर्क

अचानक धन लाभ हो सकता है। रुका हुआ पैसा मिलने के योग हैं। पैसों के मामले सुलझ सकते हैं। दोस्त आपको समस्याओं से बाहर निकलने में मदद करेंगे।

सिंह

आप धार्मिक विचारों वाले होंगे और कुछ पवित्र कर्म करेंगे, जिसके लिए आपकी सामाजिक लोकप्रियता बढ़ेगी। आपका पारिवारिक-जीवन आनंदित रहेगा और आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे।

कन्या

आज आपका दिन शानदार रहेगा। लोग आपकी बातों पर पूरा ध्यान देंगे। यात्रा की योजना बन सकती है। पैसों की कुछ उलझी हुई स्थितियों का समाधान आज निकल जायेगा।

तुला

गृहस्थ जीवन में आनंद का माहौल रहेगा। परिजनों के साथ घर के प्रश्नों के सम्बंध में चर्चा करेंगे। बुजुर्गों का स्नेह मिलेगा। व्यवसाय में अप्रत्याशित लाभ की संभावना है।

वृश्चिक

आपके लिए दिन खास रहेगा। कुछ ऐसी बातें या चीजें सामने आ सकती हैं, जो आपको आने वाले दिनों में बड़ा फायदा देंगी। किसी कठिन मामले को सुलझाने के लिए अच्छा दिन है।

धनु

व्यावसायिक सन्दर्भ में आज आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल कर कुछ जोखिम लेने की सकते हैं। हालांकि आपके लिए अपनी इस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना उत्तम रहेगा।

मकर

आज का दिन आपके लिये मिला-जुला रहेगा। किसी जरूरी चीज को खरीदने में आपके पैसे खर्च हो सकते हैं। इस राशि के जो लेखक हैं, उनकी किसी कविता की प्रशंसा हो सकती है।

कुम्भ

आज आपको माता-पिता का सहयोग प्राप्त होगा। आप खाली समय का आनंद ले सकेंगे। मनोरंजन और एशो-आराम के साधनों पर जरूरत से ज्यादा खर्च न करें। पत्नी की भावनाओं को समझेंगे।

मीन

आज आप जो भी काम करेंगे उससे आपको कुछ न कुछ फायदा तो होगा ही। कामकाज से आपको पैसा मिलेगा। मन में पैसों को लेकर कई तरह के विचार आ सकते हैं।

बॉलीवुड | मन की बात

फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं रणबीर कपूर

रणबीर कपूर ने अपनी अपकमिंग फिल्म शमशेरा के प्रमोशन में एक खुलासा किया है। एक इंटरव्यू में रणबीर ने बताया कि वो एक फिल्म डायरेक्ट करना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने लॉकडाउन के दौरान एक स्टोरी भी लिखी है। साथ ही एक्टर ने कहा कि इस फिल्म को आलिया भट्ट प्रोड्यूस कर सकती हैं। रणबीर ने कहा मैंने अनुराग बसु के साथ मिलकर जग्गा जासूस को प्रोड्यूस किया था, मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं था। मैंने उस फिल्म को एक एक्टर के तौर पर प्रोड्यूस किया था। इसलिए अभी तक मैंने प्रोड्यूसर के तौर पर काम नहीं किया है, लेकिन हां मैं हमेशा से एक फिल्म डायरेक्ट करना चाहता हूं। रणबीर ने आगे कहा, मैंने इस लॉकडाउन में एक स्टोरी भी लिखी है। कहानी मुझे काफी पसंद आई, लेकिन मुझे लिखना नहीं आता। इसलिए मैं अपनी स्टोरी को लोगों के साथ शेयर करूंगा और उनके साथ एक फिल्म बनाउंगा। प्रोडक्शन से ज्यादा मैं डायरेक्शन करना चाहता हूं। मेरी वाइफ एक बहुत अच्छी प्रोड्यूसर है, तो हो सकता है कि वो मेरी फिल्म प्रोड्यूस करे। बता दें, रणबीर कपूर और आलिया भट्ट ने हाल ही में सोशल मीडिया के जरिए अपनी प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी। कपल की शादी इसी साल 14 अप्रैल को फैमिली और फ्रेंड्स के बीच हुई थी। रणबीर और आलिया अयान मुखर्जी की फिल्म ब्रह्मास्त्र में एक साथ पहली बार नजर आएंगे। रणबीर के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स में लव रंजन की अनटाइटल्ड रोमांटिक कॉमेडी फिल्म है। इसमें वे श्रद्धा कपूर के साथ नजर आएंगे। इसके साथ ही करण मल्होत्रा के डायरेक्शन में बनी फिल्म शमशेरा में भी रणबीर टाइटल रोल निभा रहे हैं, जो 22 जुलाई को रिलीज होगी। इसमें रणबीर के साथ वाणी कपूर और संजय दत्त भी हैं।

तीन महीने बाद होगी अथिया-राहुल की शादी!

भारतीय क्रिकेट टीम के बल्लेबाज केएल राहुल और एक्टर सुनील शेट्टी की बेटी अथिया शेट्टी अक्सर अपने रिलेशनशिप को लेकर चर्चा में बने रहते हैं। एक दिन पहले खबर आई थी कि राहुल और अथिया तीन महीने बाद शादी करने वाले हैं। अब इन खबरों पर अथिया शेट्टी और सुनील शेट्टी ने रिएक्ट किया है। अथिया ने सोशल मीडिया स्टोरी पर एक पोस्ट शेयर कर लिखा मुझे उम्मीद है कि मुझे तीन महीने में होने वाली इस शादी में इनवाइट किया जाएगा। इससे पहले खबरों में यह बताया गया था कि अथिया और राहुल दोनों की फैमिली ने उनकी शादी की तैयारियां करना भी शुरू कर दिया है। वहीं अथिया और राहुल की शादी की खबरें सुनने के बाद सुनील शेट्टी ने बताया कि सच जानने के बाद दोनों के फैंस का दिल टूटने वाला है। उन्होंने तीन महीने बाद अथिया और राहुल की शादी की खबरों को अफवाह बताकर उसे खारिज कर दिया। इतना ही नहीं, सुनील ने कहा कि फिलहाल अथिया की शादी की कोई प्लानिंग नहीं है, ना ही कोई तैयारियां चल रही हैं। सूत्रों ने बताया था कि अथिया और राहुल 3 महीने बाद शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। एक्ट्रेस के एक करीबी सूत्र ने बताया था कि अथिया शेट्टी और केएल राहुल तीन साल से ज्यादा समय से एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब दोनों अगले तीन महीनों के बाद अक्टूबर या नवंबर में एक-दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हैं। दोनों की शादी की तैयारियां जोरों पर चल रही हैं। एक सूत्र ने यह भी बताया था कि राहुल के माता-पिता हाल ही में अथिया की फैमिली से मिलने के लिए मुंबई आए थे। इतना ही नहीं, राहुल और अथिया दोनों अपनी फैमिली के साथ अपने नए घर को देखने भी गए थे। दोनों अपने नए घर में चल रहे काम की प्रोग्रेस को देखने के लिए वहां पहुंचे थे। कपल की शादी अगले तीन महीने बाद मुंबई में होने की उम्मीद है। दोनों परिवारों के लिए यह एक ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा। शादी की हर तैयारियों की देखरेख खुद होने वाली दुल्हन अथिया कर रही हैं। बता दें कि कुछ दिन पहले

बॉलीवुड | गपशप

केएल राहुल ट्रीटमेंट के लिए जर्मनी गए थे, उनके साथ अथिया शेट्टी भी वहां गई थीं। इंजरी के कारण राहुल इंडिया के इंग्लैंड टूर से बाहर हो गए थे। 30 साल के राहुल को कमर में चोट आई थी, जिसकी सर्जरी कराने के लिए वे जर्मनी गए थे।

कॉफी विद करण : 22 एपिसोड होस्ट करेंगे करन जौहर

पॉपुलर सेलिब्रिटी चैट शो कॉफी विद करण का सीजन सात शुरू हो चुका है। 7 जुलाई से स्टार्ट हुए इस शो को इस बार ओटीटी प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर स्ट्रीम किया जा रहा है। चैट शो के हर सीजन को लोगों ने खूब पसंद किया है। वहीं इस सीजन को लेकर भी दर्शकों की उम्मीदें हाई हैं। वहीं रिपोर्ट्स की मानें तो करण जौहर एक ऐपिसोड को होस्ट करने के लिए 1-2 करोड़ तक की फिस चार्ज कर रहे हैं। कॉफी विद करण की शुरुआत

साल 2004 में हुई थी। सीजन 7 के साथ ही ये शो भारत में सबसे लंबे समय तक चलने वाले शो में से एक बन गया है। कॉफी विद करण के हर सीजन में करण लगभग 20 एपिसोड होस्ट करते हैं। पर इस सीजन में वो 22 एपिसोड होस्ट कर सकते हैं। सीजन 7 के लिए करण 40 करोड़ रुपए चार्ज कर रहे हैं। कह सकते हैं कि इस शो को हिट बनाने का पूरा क्रेडिट करण जौहर और उनकी होस्टिंग को जाता है। विवादों को आग की तरह भड़काने वाले इस टॉक शो में इस बार फैमिली मैन स्टार सामंथा रूथ प्रभु एक्टर अक्षय कुमार के साथ काउच शेयर करती नजर आने वाली हैं, जहां वो अपने एक्स हस्बेंड नागा चैतन्य के साथ हुए तलाक के बारे में बात करती दिखाई देने वाली हैं। वहीं एक एपिसोड में वरुण धवन अपनी फेवरेट सेक्स पोजीशन के बारे में डिसकस करते दिखाई देंगे। जबकि सारा अली खान एक एपिसोड में ये कहती नजर आने वाली हैं कि उनका एक्स बॉयफ्रेंड सभी के एक्स हैं। इन सबके अलावा इस शो में अनन्या पांडे, विजय देवरकोंडा, कियारा आडवाणी और शाहिद कपूर जैसे कई सितारे नजर आने वाले हैं।

बॉलीवुड | मसाला

अजब-गजब | यहां पर खोजने से भी नहीं मिलते सांप

इस देश में इंसानों से ज्यादा हैं भेड़

दुनिया के नक्शे पर छोटे-बड़े सैकड़ों देश हैं और उनकी अपनी-अपनी भौगोलिक परिस्थितियां हैं। हर जगह की अपनी खासियत है और इसके जरिये वो अपनी अलग पहचान रखता है। दुनिया में कई देशों के बारे में तो हमें पता है, लेकिन कुछ देशों की विशेषताओं को लेकर हम आज भी अनभिज्ञ है। मसलन न्यूज़ीलैंड का नाम सभी ने सुना होगा, लेकिन इससे जुड़े जो दिलचस्प तथ्य हम आपको बताने जा रहे हैं, वो आपने नहीं सुने होंगे। न्यूज़ीलैंड की गिनती सबसे खूबसूरत देशों में होती है। प्राकृतिक दृश्यों और जंगलों के बारे में बात की जाए, तो ये देश काफी हरा-भरा है। लोग यहां मौजूद सुंदर नज़ारे देखने के लिए दुनिया भर से आते हैं। इतना ही नहीं ये ऐसा देश है, जहां कोई भी काम शुरू करना हो तो आपको ज्यादा पेपरवर्क नहीं करना पड़ता। इतनी सारी खासियत होने के बाद भी आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां की जनसंख्या बहुत कम है।

न्यूजीलैंड दुनिया का अकेला देश है, जहां इंसानों की आबादी भेड़ों से भी कम है। देश में कुल रहने वाले लोगों की संख्या 48 लाख के आसपास है। इस देश में भेड़ों की भी आबादी कम नहीं है। न्यूज़ीलैंड में एक इंसान पर औसतन पांच भेड़ें मौजूद हैं। पहले ये संख्या 8-10 भेड़ें/व्यक्ति थी, जो अब घटकर 5 भेड़ों तक रह गई है। भेड़ें ज्यादा होने की वजह से इस देश में हर आदमी के लिए 100 किलो मक्खन और 65 किलो चीज का उत्पादन होता है। इतना ही नहीं न्यूजीलैंड की एक और खासियत ये है कि यहां पर भेड़ें इतनी सारी हैं, लेकिन सांप एक भी नहीं हैं। घने जंगल होने के बाद भी सांप मिलना बेहद मुश्किल है। अगर कहीं ये दिख भी जाए, तो इसे पुलिस के हवाले करना होता है। लेबनान से थोड़ी दूरी पर मौजूद देश साइप्रस को बिल्लियों का द्वीप कहा जाता है। साइप्रस में रहने वाले लोगों की कुल जनसंख्या 12 लाख से कुछ ज्यादा बताई जाती है, लेकिन यहां रहने वाली बिल्लियों की जनसंख्या 15 लाख के आस-पास है। सोचिए, इंसानों से 1-2 लाख ज्यादा ही बिल्लियां इस जगह पर रहती हैं। मज़े की बात तो ये है कि बिल्लियों के रहने से यहां के लोगों को कोई दिक्कत नहीं है बल्कि उन्हें इनके साथ रहने की आदत पड़ चुकी है।

ये है दुनिया का सबसे महंगा चिप्स, शराब से होता है तैयार

मार्केट में कई तरह के चिप्स आपको मिल जायेंगे। ये अलग अलग शेप और पैकेट्स के होते हैं। साथ ही क्वांटिटी के हिसाब से इनकी कीमत फिक्स होती है। लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे महंगे चिप्स के बारे में बताने जा रहे हैं। अमेरिका के एक रेस्त्रां ने इस सबसे महंगे चिप्स की प्लेट को अपने मेन्यू में शामिल किया है। इसे अमेरिका के नेशनल फ्रेंच फ्राई डे पर मेन्यू में ऐड किया गया है। इसकी एक प्लेट की कीमत आपको हैरान कर देगी। न्यूयार्क में स्थित इस रेस्त्रां का नाम Serendipit43 है। इस रेस्त्रां का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है। ये रेस्त्रां अपने शैम्पेन में डुबाकर सुखाए गए आलू के चिप्स के लिए जाना जाता है। चिप्स की इस प्लेट पर सोने का बुरादा छिड़का जाता है। रेस्त्रां ने बीच में इसे अपने मेन्यू से निकाल दिया था। लेकिन 13 जुलाई को अमेरिका में सेलिब्रेट होने वाले नेशनल फ्रेंच फ्राई डे पर इसे वापस से ऐड किया गया। इसकी एक प्लेट की कीमत आपको 16 हजार रुपए पड़ेगी। रेस्त्रां ने खुद अपने इस महंगे चिप्स की प्लेट की कीमत बताई। साथ ही ये भी रिवील किया कि आखिर इस चिप्स में क्या-क्या मिलाया जाता है? इंग्रीडिएंट देखने के बाद समझ आएगा कि इसे बनाने में किसी भी तरह की कंजूसी नहीं की गई है। तमाम तरह की महंगी चीजों से इसे तैयार किया जाता है। अब रेस्त्रां ने अपने इस महंगे डिश के बारे में एक और घोषणा की है। अपने इंस्टाग्राम पेज पर रेस्त्रां ने कंफर्म किया कि उन्होंने नेशनल फ्रेंच फ्राई डे पर दुनिया के सबसे महंगे फ्राइज को अपने मेन्यू में शामिल किया है। इसकी कीमत 168 पाउंड यानी करीब 16 हजार रुपए है। रेस्त्रां ने इस चिप्स में इस्तेमाल होने वाले इंग्रीडिएंट के बारे में बताया। इस चिप्स को बनाने में चिपरबेक आलू का इस्तेमाल किया गया। इसके अलावा इसमें Dom Perignon शैम्पेन और J। LeBlanc French Champagne Ardenne विनेगर का इस्तेमाल किया गया है। साथ ही इस चिप्स में Guerande ट्रफल नमक और rbani summer truffle तेल का इस्तेमाल किया गया है। ये सारे इंग्रीडिएंट काफी महंगे आते हैं। इसके अलावा सर्व करते हुए इस चिप्स पर सोने का बुरादा छिड़का जाता है। इस वजह से इसकी पर प्लेट कीमत इतनी ज्यादा है।

स्वास्थ्य और पीडब्ल्यूडी में हुए तबादलों में गड़बड़ियों पर एक्शन में सरकार, जांच शुरू

» सात दिन में रिपोर्ट पेश करेंगी जांच समितियां दस्तावेज तलब

» स्वास्थ्य विभाग के तबादलों को लेकर डिप्टी सीएम ने अपर मुख्य सचिव से मांगा था स्पष्टीकरण

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। स्वास्थ्य और लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) में हुए तबादलों में हुई गड़बड़ियों के खुलासे के बाद सरकार एक्शन में आ गयी है। सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश के बाद मामले की जांच शुरू हो गई है। दोनों विभागों में हुए तबादलों की जांच के लिए गठित उच्च स्तरीय समितियों ने अपना काम शुरू कर दिया है। ये समितियां इसकी रिपोर्ट सात दिन में देंगी।

दोनों समितियों ने संबंधित विभागों में तबादलों से जुड़ी फाइलें और अभिलेख तलब कर लिए हैं। संभावना जतायी जा रही है कि जांच समितियां फाइलों का परीक्षण कर गुरुवार को अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपेंगी। स्वास्थ्य विभाग में प्रांतीय चिकित्सा सेवा संवर्ग के लगभग 2500 डाक्टरों के तबादले हुए हैं। इनमें 450 से अधिक तबादलों को लेकर शिकायतें हुई थीं। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की जिम्मेदारी संभाल रहे उप मुख्यमंत्री बृजेश पाठक ने इस संदर्भ में विभाग के अपर मुख्य सचिव अमित मोहन प्रसाद को पत्र लिखकर उनसे स्पष्टीकरण मांगा था।

मामले के तूल पकड़ने पर मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों के तबादलों में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्र की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित करने का निर्देश दिया था। समिति ने स्वास्थ्य विभाग से फाइलें तलब कर जांच कार्य शुरू कर दिया है। उधर, लोक निर्माण विभाग के अभियंताओं के तबादलों में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए कृषि उत्पादन आयुक्त मनोज कुमार सिंह और अपर मुख्य सचिव आबकारी संजय भूसरेड्डी की दो सदस्यीय समिति ने भी काम शुरू कर दिया है। समिति ने लोक निर्माण मुख्यालय से तबादलों से जुड़ी सभी फाइलें मंगा ली हैं और उनका परीक्षण कर रही है।

प्रमोद कृष्णम ने किया द्रौपदी मुर्मू का समर्थन कांग्रेस को दी नसीहत

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

» पार्टी आलाकमान को पुनर्विचार को कहा

नई दिल्ली। कांग्रेस के सीनियर नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राष्ट्रपति चुनाव के लिए एनडीए प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने कांग्रेस हाईकमान को नसीहत भी दी है। इस संबंध में प्रमोद कृष्णम ने एक ट्वीट किया है।

प्रमोद कृष्णम ने बुधवार रात को ट्वीट कर लिखा कि पंडित मोतीलाल नेहरु से लेकर आज तक कांग्रेस हमेशा शोषित, वंचित और आदिवासियों के साथ खड़ी रही है। राष्ट्रपति चुनाव में एक आदिवासी महिला उम्मीदवार द्रोपदी मुर्मू का विरोध करना मेरे विचार से बिलकुल उचित नहीं है। पार्टी हाई कमान को इस पर पुनर्विचार करना चाहिये। प्रमोद कृष्णम के इस ट्वीट पर अभी तक किसी कांग्रेस नेता की प्रतिक्रिया नहीं आई है।

लखीमपुरखीरी कांड

आशीष मिश्रा की जमानत पर अब 15 को सुनवाई

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

» सरकार ने जमानत का किया विरोध

लखनऊ। लखीमपुरखीरी के तिकुनिया कांड मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के पुत्र आशीष मिश्रा उर्फ मोनू की जमानत याचिका पर हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ में बुधवार को भी सुनवाई पूरी न हो सकी। अब 15 जुलाई को इस मामले की सुनवाई होगी। जस्टिस कृष्ण की एकल पीठ के समक्ष राज्य सरकार ने आशीष मिश्रा की जमानत का विरोध किया था।

अभियुक्त की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल चतुर्वेदी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से बहस की। उन्होंने दलील दी कि सर्वोच्च न्यायालय ने आशीष मिश्रा की जमानत पर दोबारा सुनवाई का आदेश दिया है। इसका आशय यह नहीं लगाया जाना चाहिए कि शीर्ष अदालत ने जमानत याचिका के विरुद्ध कोई टिप्पणी की है। 197 स्थानीय लोगों ने शपथ पत्र देकर जांच एजेंसी को बताया है कि घटना के वक्त आशीष मिश्रा दंगल में मौजूद था। यह भी दलील दी गई कि स्वयं अभियोजन पक्ष ने गाड़ी चढ़ाने का आरोप ड्राइवर पर लगाया है जिसका अर्थ है कि जिन चार लोगों की जान थार गाड़ी चढ़ने की वजह से गई है, उनकी हत्या आशीष मिश्रा ने नहीं की है। पीड़ित पक्ष की ओर से भी तर्क रखा गया। हालांकि, समय की कमी की वजह से बहस पूरी नहीं हो सकी।

कुमार विश्वास की बढ़ाई गई सुरक्षा अब वाई प्लस कैटेगरी की सिक्योरिटी

» एजेंसियों की रिपोर्ट पर बढ़ाया गया सुरक्षा घेरा तैनात रहेंगे 11 जवान

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

नोएडा। देश के चर्चित युवा कवि और आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता कुमार विश्वास की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। कुछ अलगाववादी तत्वों और असामाजिक तत्वों से खतरे के मद्देनजर उनकी सुरक्षा व्यवस्था पहले की अपेक्षा अब ज्यादा बढ़ा दी गई है। केंद्र सरकार ने अब कुमार विश्वास को वाई प्लस कैटेगरी की सुरक्षा देने का फैसला किया है। केंद्र सरकार ने इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर कुमार विश्वास की सुरक्षा घेरा को बढ़ाने का फैसला किया है।

पिछले कुछ समय से कुमार विश्वास की सुरक्षा व्यवस्था से सम्बंधित मसले पर केंद्रीय खुफिया एजेंसी आईबी समेत स्थानीय पुलिस अधिकारियों द्वारा केंद्र सरकार को कुछ विशेष इनपुट्स मिले थे। यही वजह है कि कुमार विश्वास की सुरक्षा को बढ़ाने का फैसला केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा लिया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा जारी निर्देश के मुताबिक, कुमार विश्वास की सुरक्षा श्रेणी 'वाई' से अपग्रेड करके अब 'वाई प्लस' कर दी गई है। वाई प्लस श्रेणी के तहत कुमार विश्वास की सुरक्षा में सीआरपीएफ के जवान, कमांडो सहित स्थानीय पुलिस की टीम तैनात रहेगी। कुमार विश्वास के साथ 24 घंटे अर्धसैनिक बल सीआरपीएफ के दो कमांडो की तैनाती हमेशा रहेगी। इसके साथ ही 11 जवानों की ड्यूटी शिफ्ट वाइज चेंज होती रहेगी। पिछले साल ही कुमार विश्वास को वाई श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई थी, जिसके तहत 4 जवानों की तैनाती होती थी, लेकिन अब वाई प्लस की सुरक्षा व्यवस्था मिल जाने के बाद 11 जवानों की तैनाती उनके साथ रहेगी।

कोरोना वैक्सीन की फ्री बूस्टर डोज कल से

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

75 दिनों तक चलेगा विशेष अभियान

नई दिल्ली। सभी वयस्कों को कोरोना वैक्सीन की सतर्कता डोज मुफ्त में लगेगी। सरकार इसके लिए 15 जुलाई से 75 दिनों तक विशेष अभियान चलाएगी। आजादी के अमृत महोत्सव को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में इसे हरी झंडी दे दी गई। अभी तक सिर्फ 60 से अधिक उम्र के बुजुर्गों, हेल्थ व फ्रंटलाइन वर्कर्स के लिए ही सतर्कता डोज मुफ्त में देने का प्रावधान था।

सूचना व प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि 18 से 59 साल तक के वयस्कों के लिए कोरोना वैक्सीन की सतर्कता डोज मुफ्त में देने का फैसला लिया गया है। यह डोज सिर्फ सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर में ही लगेगा। निजी अस्पतालों व डिस्पेंसरी में सतर्कता डोज लेने की स्थिति में पहले की तरह इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। कोरोना के कई वैरिएंट इस समय सामने आ चुके हैं। हर वैरिएंट का अलग असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में वैक्सीन की दो डोज लगवाने के बाद भी लोगों की इम्यूनिटी कमजोर पड़ने लगती है। कोरोना की तीसरी लहर के दौरान भी संक्रमण के कई मामले देखने को मिले थे। ऐसे में उसी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज निकाली गई है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी, इसके अलावा कोरोना होने के बाद भी गंभीर लक्षण देखने को नहीं मिलेंगे।

तो नौकरशाह चला रहे हैं प्रदेश की सरकार!

» 4पीएम की परिचर्चा में प्रबुद्धजनों ने उठाए सवाल

4पीएम न्यूज़ नेटवर्क

लखनऊ। यूपी में आजकल तबादलों और घोटालों का मानो सीजन चल रहा है। अफसर मनमानी कर रहे है। स्वास्थ्य विभाग और पीडब्ल्यूडी विभागों के तबादले को लेकर जांच कमेटी बना दी गयी है। ऊर्जा विभाग के चैयरमैन मंत्री की नहीं सुन रहे। ऐसे में बड़ा सवाल यह कि नौकरशाह इतने बेकाबू क्यों हो रहे है? इस मुद्दे पर वरिष्ठ पत्रकार अजय शुक्ला, डॉ. उत्कर्ष सिन्हा, सैयद कासिम, सुशील दुबे, अनिल रॉयल और 4पीएम के संपादक संजय शर्मा ने एक लंबी परिचर्चा की।

परिचर्चा
रोज शाम को छह बजे देखिए 4PM News Network पर एक ज्वलंत विषय पर चर्चा

सुशील दुबे ने कहा कमिश्नर रंजन कुमार की जो स्टोरी की है 4पीएम ने उसने एलडीए के एक करोड़ रुपए बचा दिए। योगी पार्ट वन में लिखी गई बृजेश पाठक की चिट्ठी अब काम कर गई, उन्हें नहीं पता था कि आने वाले समय में यही लोग मेरे सिरदर्द बनेंगे कि अमित मोहन प्रसाद मेरी ही नहीं सुनेंगे। डॉ. उत्कर्ष सिन्हा ने कहा यूपी में नौकरशाहों का जलवा कोई नई बात नहीं है। स्वास्थ्य विभाग में बड़े-बड़े मठाधीश हैं। निदेशालय और शासन स्तर पर बड़े खेल होते हैं। सैयद कासिम ने कहा कि बृजेश पाठक और एके शर्मा दोनों ने सवाल उठाए शायद योगीजी ने ये मान लिया है कि मंत्री आपकी मर्जी से और अधिकारी मेरी मर्जी के। पाठक की चिट्ठी इतनी आसानी से मरने वाली नहीं है। अनिल रॉयल ने कहा, स्वास्थ्य विभाग में लूट खसोट मची हुई है। बृजेश पाठक की छवि पूरे प्रदेश में बढ़ी है। अजय शुक्ला ने कहा आज मंत्री लिख रहा हमारे विभाग में....वगैरा वगैरा। सरकार ब्यूरोक्रेसी चला रही। इसका मतलब राज्य का मुख्यमंत्री अयोग्य है।

मुख्यमंत्री से सांसद रवि किशन की शिकायत

गृह प्रवेश में काम कराया पर नहीं दी मजदूरी, सीएम योगी से गुहार, पैसे नहीं मिले तो करेंगे आत्मदाह

जनता दरबार में मजदूरों ने सांसद पर लगाए गंभीर आरोप

4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। गोरखपुर में मजदूरों ने सांसद रवि किशन के खिलाफ सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ से शिकायत की है। शिकायत में मजदूरों ने कहा है कि भाजपा सांसद ने अपने गोरखपुर वाले घर में गृह प्रवेश के दौरान काम करवाया लेकिन उन्हें इसका पैसा नहीं दिया गया। कल जनता दरबार में मजदूरों ने सीएम योगी के सामने प्रार्थना पत्र देते हुए अपनी शिकायत की।

प्रार्थना पत्र में मजदूरों ने बताया हि भाजपा सांसद रवि किशन ने अपने गोरखपुर वाले घर के गृह प्रवेश में हमने काम किया। लेकिन उस काम की मजदूरी अभी तक नहीं दी गई। अगर हमें पैसे नहीं मिले तो हम मजबूरन आत्मदाह कर लेंगे। मजदूरों की शिकायत पर सीएम योगी ने जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। मजदूरों का कहना है कि बकाया पैसा मांगने पर रवि किशन अपने सहयोगियों से लेने की बात करते हैं, जबकि उनके सहयोगी पैसा मांगने पर धमकी देते हैं। सांसद के सहयोगी कहते हैं तुम लोगों को मारकर बंद करा देंगे। बता दें कि सांसद रवि किशन ने गोरखपुर में नौकायान के पास नया घर बनवाया है। इसी घर में 11 जून को गृह प्रवेश का कार्यक्रम था, जिसमें मनोज निषाद, सुधीर जायसवाल, संदीप कुमार, विवेक पासवान, धीरज, गोलू पासवान, निखिल पासवान सहित 15 से 20 मजदूरों ने काम किया था। वे गोरखनाथ मंदिर पहुंचे थे। पैसे न मिलने पर मजदूरों ने योगी के जनता दरबार में गोरखपुर सांसद पर गंभीर आरोप लगाए।

ढाई लाख के काम में दिए सिर्फ 40 हजार

मजदूरों का आरोप है कि कार्यक्रम की पूरी जिम्मेदारी सांसद के सहयोगी समरेंद्र बहादुर सिंह, जय यधुवंशी, पवन दूबे और अभिषेक जायसवाल ने ली थी, जिसमें वेटर, माली, लाइट, साउंड, टेंट, डिस्पोजल आईटम आदि का काम 2.48 लाख में तय हुआ था, जिसमें सांसद की टीम ने मजदूरों को 40 हजार रुपए एडवांस के तौर पर दिया था। लेकिन काम पूरा होने के बाद बाकी की बची रकम नहीं मिली। सांसद के पीआरओ पवन दुबे का कहना है कि मजदूरों का आरोप पूरी तरह बेबुनियाद है। जिन मजदूरों ने आरोप लगाया है, उन्हे आर्डर तो दिया गया था, लेकिन उनसे काम नहीं कराया गया था। उनकी जगह दूसरे टेंट हाउस से बात करके काम कराया गया।

> "हमें इस बात की कोई जानकारी नहीं है। हम लोग गरीबों की मदद करते हैं। अगर किसी का भी कोई बकाया है तो वह सीधा मुझसे बात करके अपना पेमेंट ले सकता है। बाकी सभी आरोप पूरी तरह गलत हैं। -रवि किशन, सांसद

फोटो: 4पीएम

जलाभिषेक लखनऊ। राजधानी में आस्था का सावन आ गया है। शहर के हर मंदिरों में ॐ नमः शिवाय की धूम है। शहर का कोना कोना हर हर बम बम के उद्घोष में डूबा हुआ है। आज सुबह मनकामेश्वर मंदिर में हजारों श्रद्धालुओं ने बाबा दरबार में हाजिरी लगाई और भगवान शिव का जलाभिषेक किया।

सुप्रीम कोर्ट के आदेशों की अवमानना कर रही यूपी सरकार : आजम खां

शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से एक हफ्ते में मांगा जवाब

4पीएम न्यूज नेटवर्क

नई दिल्ली। सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान ने उत्तर प्रदेश की राज्य सरकार पर सुप्रीम कोर्ट की अवमानना करने का आरोप लगाया है। इस मामले में शीर्ष अदालत ने राज्य सरकार से एक हफ्ते में जवाब मांगा है।

समाजवादी पार्टी नेता आजम खान ने आज सुप्रीम कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी का रास्ता बंद कर दिया है। इसलिए यूनिवर्सिटी में जाना मुश्किल हो रहा है और सारा काम रूक गया है। वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यूनिवर्सिटी के मुख्य द्वार पर तारों से घेरा बांध दिया गया है। इसकी वजह से यूनिवर्सिटी के अंदर कोई नही जा सकता। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने यूनिवर्सिटी में यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था लेकिन तारों की घेराबंदी इस तरह की गई है कि यूनिवर्सिटी में जाना ही संभव नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना है। सिब्बल ने इस बाबत तस्वीरें भी कोर्ट को दिखाई। इससे पहले हाईकोर्ट ने कुछ हिस्से की जमीन को जब्त करने का आदेश दिया था लेकिन 27 जून को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट आदेश पर रोक लगाते हुए यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया था।

फोटो: 4पीएम

पुष्पांजलि राजधानी लखनऊ में पूर्व मुख्यमंत्री चंद्र भानु गुप्ता के जन्मदिवस पर मोती महल में हवन करते लोग व उनकी समाधि पर पुष्पांजलि करते हुए।

प्रदेश में जल्द शुरू होंगे 16 आयुष अस्पताल : दयालु

मंत्री बोले, आयुष कॉलेजों की फीस निर्धारित

4पीएम न्यूज नेटवर्क

लखनऊ। खाद्य सुरक्षा एवं आयुष मंत्री दयाशंकर मिश्र दयालु ने कहा कि आयुष कॉलेजों की फीस निर्धारित कर दी गई है। स्नातक में 100 सीट वाले कॉलेज हर साल डेढ़ लाख और 60 सीट वाले कॉलेज एक लाख 30 हजार फीस ले सकेंगे। अब सभी कॉलेज महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय से संबद्ध किए जाएंगे।

अब तक 105 कालेजों का समृद्धि करण किया जा चुका है। 100 दिन की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए आयुष मंत्री ने बताया कि किसानों को औषधीय खेती के प्रति जागरूक करने और औषधीय पौधों का मूल्य दिलाने के लिए कांट्रैक्ट फार्मिंग शुरू कराई जा रही है। इसकी नीति तैयार कर केंद्र सरकार को भेजी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में सात आयुर्वेदिक और नौ होम्योपैथिक चिकित्सालय का भवन निर्माण पूरा हो गया है जल्द ही इनका उद्घाटन किया जाएगा। मंत्री दयालु ने कहा कि पिछले साल विभिन्न स्थानों पर छापेमारी करके 29 तरुण की वसूली की गई है। प्रदेश के साथ मंडल में सचल खाद्य जांच प्रयोगशाला संचालित की जा रही है। इन मंडल के जिलों में सचल दल जाकर नमूने ले रहा है। झांसी एवं देवीपाटन मंडल में क्षेत्रीय खाद्य प्रयोगशाला का निर्माण कार्य शुरू कराया गया है।

स्वामी, मुद्रक एवं प्रकाशक **बबिता चतुर्वेदी** के लिए **4पीएम** आस्था प्रिंटर्स, 5/600, विकास खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ (यूपी) से मुद्रित एवं प्रकाशित। **प्रधान संपादक**- अर्चना दयाल, **संपादक** - संजय शर्मा, **स्थानीय संपादक** - सूर्यकांत त्रिपाठी*, **विधि सलाहकार**: सत्यप्रकाश श्रीवास्तव, मोहम्मद हैदर, **वित्तीय सलाहकार**: संदीप बंसल, **कार्टूनिस्ट**: हसन जैदी, **दूरभाष**: 0522- 4078371 | **Email**: daily4pm@gmail.com | **website:** www.4pm.co.in | **RNI-UPHIN/2015/62233** डाक पंजी. सं- SSP/LW/NP-495/2018-2020
*इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद लखनऊ न्यायालय के अधीन ही होंगे।